WWJMRD 2015; 1(5): 53-56
www.wwjmrd.com
International Journal
Peer Reviewed Journal
Refereed Journal
Indexed Journal
Impact Factor MJIF: 4.25
E-ISSN: 2454-6615

संदीप सिंह चौहान
विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान
विभाग राजकीय महाविद्यालय
बांरा, राजस्थान, भारत

भारतीय राजनीति में अपराधीकरण का बढ़ता प्रभाव (सामान्य विश्लेषण)

संदीप सिंह चौहान

शोध सांराश–
सारा प्रशासन प्राथमिक रूप से उनकी सुख–सुविधाओं के लिए बना है। इसी धारणा से विशिष्ट वर्ग मुफ्तखोरी करने, शासन का व्यक्तिगत–पारिवारिक सुविधाओं के लिए प्रयोग करने, सिफारिश, भाई–भतीजावाद आदि के रास्ते अपने निजी अधिकर बढ़ाने आदि की जो प्रवृत्ति शुरू होती हैं वह पार्टी और व्यक्ति के भेद को मिटाती है। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कमीशन खाने, धोखाधड़ी करने की प्रवृत्ति राजनीति को सफेदपोश और नकाबधारी अपराधियों का जमावड़ा बना देती है। उनके मुँह और लेखन में नैतिकता की बात सन्देह पैदा करने लगती है। उनके कामों में ईमानदारी, प्रतिबद्धता और जनता के प्रति लगाव अब अपवाद स्वरूप ही देखे जा सकते हैं। अतः भ्रष्टाचार और राजनीति में अपराधीकरण की बीमारी से निपटने के लिए जो नीतिगत खामियां और प्रशासनिक लापरवाही है, उससे निजात पाने का कोई सार्थक संघर्ष कहीं भी नहीं दिख रहा है। अतः बदलते आपराधिक राजनीतिक परिवेश में इस पर ठोस कदम उठाना आवश्यक ही बल्कि अपरिहार्य है।

Keywords: परिदृश्य, सुशासन, अदालतों, विशिष्ट, गतिविधियों

शोध विस्तार–
भारत में वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि राजनीति में अपराधीकरण दिनों–दिन बढ़ता जा रहा है। इससे न केवल राजनीतिक मर्यादाओं का ह्रास हो रहा है बल्कि यह सुशासन के प्रयासों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। इस दिशा में सुधारों के लिये सरकार द्वारा एक अभिनव प्रयास राजनीतिज्ञों से जुड़े आपराधिक मामलों के त्वरित निपटाने के लिये त्वरित अदालतों' (फॉस्ट ट्रेक) का गठन है।
लोकतांत्रिक सुधारों से संबंधित एक संगठन के अनुसार, वर्तमान लोकसभा के 34 प्रतिशत सदस्यों पर आपराधिक मुकद्दमें दर्ज है तथा राज्यों के संदर्भ में तो यह स्थिति और भी भयावह है। ये विशिष्ट वर्ग ही अपने व्यक्तिगत हित के लिये न सिर्फ कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं बल्कि राजनीति व प्रशासन में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी आदि के माध्यम से राजनीति को अपराधियों का जमावड़ा बना देते हैं। राजनीति में बढ़ती इस प्रकार की गतिविधियों से सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र ही दूषित नहीं हो रहा है बल्कि इसने देश में सुशासन की स्थापना को भी असंभव सा बना दिया है।[1]
राजनीति में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ने से पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समानता का समावेश तथा विधि का शासन जैसे प्रमुख सुशासन के तत्त्वों की प्राप्ति संभव नहीं है। साथ ही, इसने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की अवधारणा को भी कमजोर किया है।
भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में राजनीति और अपराध परस्पर इतने घुलमिल गए है कि इनके मध्य स्पष्ट विभाजन–रेखा खींचना बहुत कठिन हो गया है। राजनीति में बढ़ते अपराध पर या तो फातिहे पढ़े जाते रहे हैं अथवा नेतागण पाखण्डपूर्ण बयान देते रहते हैं अथवा घड़ियाली आँसू बहाते रहते हैं। आज स्थिति यह है कि बुद्धिजीवी, राजनीति में प्रवेश करने से डरता है, अथवा भयभीत होकर एक ओर चुपचाप बैठ गया है। जो लोग प्रवेश करते हैं अथवा उसमें टिके रहना चाहते हैं, उनके लिए आवश्यक हो गया है कि वे अपराध–जगत् का सहयोग लें। आज हालत इतनी गम्भीर है कि राजनेता चुनाव बूथों पर कब्जा करने और मतदाताओं को डरानेधमकाने के लिए गुण्डे पालते हैं। कोढ़ में खाज यह है कि ये गुण्डे कालान्तर में अपने मालिकों को ही धमका कर स्वयं राजनीति में आ रहे हैं।[2]
आज राजनीति में टिके रहने के लिए यह आवश्यक–सा बन गया है कि अपराध–जगत् का सहयोग

Correspondence:
संदीप सिंह चौहान
विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान
विभाग राजकीय महाविद्यालय
बांरा, राजस्थान, भारत

किया जाए। फलतः भारत की राजनीति में आज अनेक जाने–माने अपराधी प्रतिष्ठित हो चुके हैं। प्रायः प्रत्येक राजनीतिक दल के नेता अन्य राजनीतिक दलों माफियाओं का गिरोह बताते रहते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारे राजनीतिक जीवन में अपराधवृत्ति का समावेश आरम्भ से ही रहा है।

गांधीजी कहा करते थे कि सामाजिक सेवा की दृढ़ इच्छा रखने वाले ही राजनीति में आएं क्योंकि इसे त्याग से सींचकर पुष्पित एवं पल्लवित करना पड़ता है। परन्तु आज राजनीति आकर्षण का केन्द्र बन गई है। लोग इसे अपनी अच्छी–बुरी एवं सभी आकांक्षाओं की पूर्ति का साधन मानते हैं। आज भारतीय राजनीति जिस चौराहे पर खड़ी है, वहां इसे सिर्फ नफरत की भावना से ही देखा जाने लगा है और ऐसा स्वाभाविक भी है। वर्तमान में नेता दूसरे को नेतृत्व प्रदान करके दूसरे के नेतृत्व में काम कर रहे हैं तथा उनसे संचालित हो रहे हैं। सबसे दुःखद पहलू तो यह है कि आज भारतीय राजनीति का तीव्र गति से अपराधीकरण हो रहा है। देश की संसद तथा विधानसभाओं में अपराधियों को अपना प्रतिनिधि चुनकर जनता भेजती है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि इन अपराधियों को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ाया जाता है तथा उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है, यही नहीं मंत्रिपरिषद् में भी अपराधियों को स्थान मिलने लगा है। यह आगामी दृष्टि से राजनीति के लिए अच्छा नहीं है।'[3]

राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण तक हम जहाँ थे आज वहीं आ गये हैं। वर्तमान में लोकतंत्र की जो सामन्ती संस्कृति उभर रही है जिसमें जनता के चुने हुये प्रतिनिधि और सरकारी ति कर्मचारी राजसत्ता में उतरते ही व्यक्तिगत–पारिवारिक स्तर पर उपभोक्ता और मजे लूटने वाले बन जाते हैं।

राजनीतिज्ञ एक बार भी वोटों की वैतरणी पार कर ले और सरकारी कर्मचारी एक बार किसी तरह नियुक्ति भर पा जाएं फिर तो वे जनता के और देश के मालिक बन जाते हैं और वी.आई. पी. बनकर विशेष सुख–सुविधाओं के हकदार कानून से ऊपर और जनता से अलग विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति बन जाते हैं।

सार्वजनिक जीवन में अपनी साख खोती हुई आज की भारतीय राजनीति में अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा और परिवारवाद से घिर कर मुजरिम बनती जा रही है। इस तरह का घटनाक्रम विगत वर्षों में इतनी बार दोहराया जा चुका है कि अब लोग चौंकते नहीं और उसे राजनीति के स्वाभाविक चरित्र का हिस्सा मानने लगे हैं। अब शायद कोरे जनसेवक की छवि जो समाज के लिए अर्पित हो, राजनीति के लिए अप्रासंगिक हो गयी हैं। आज के हर दल में, हर क्षेत्र में और हर स्तर पर राजनीति का सत्ता–समीकरण और मूल्यहीन बंदरबांट साफ दिख रहा है।

इस उपक्रम में हर कोई शामिल नजर आता है। उसकी दलीय प्रतिबद्धता चाहे जो भी हो, छोटे कस्बे से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सक्रिय हर छोटे–बड़े नेता ने अपने–अपने दम–खम के हिसाब से राजनीति को अपने निजी स्वार्थ साधने का माध्यम बन लिया है। विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचने वाले नेता केवल अपने कायाकल्प तक से संतुष्ट नहीं होते हैं, वे अपने हाथ आये इस अलादीन के चिराग से अपने जन्म–जन्मांतर का साथ पूरा करने की चेष्टा करते हैं।[4]

आज स्थिति ऐसी हो गयीहै कि जन आकांक्षाओं को फलीभूत करने वाली राजनीति की संभावना मृगमरीचिका सी होती जा रही है। अपने आपको गरीब जनता का मसीहा कहलाने वाला हो या फिर साफ–सुथरी छवि वाला नेता हो आज हर कोई हवाले की हवा, स्कैम, स्कैण्डल, अपराध, घूस और चोरी जैसे आरोपों से रूबरू है। इनमें छोटे–बड़े का भेद करना मुश्किल है। सार्वजनिक जीवन में उच्च पदों पर आसीन लोगों से आशा थी कि वे अपने आचरण से लोगों को आश्वस्त करेंगे, सही दिशा देंगे और जीने की राह दिखाएंगे, पर सब कुछ उल्टा हो रहा है। भ्रष्टाचार के रूप, तकनीक और संदर्भ में विविधता होने के बावजूद इतना तो साफ जाहिर है कि इसकी जड़ें गहरी हो चुकी है और व्यवस्था तथा शासनतंत्र के छिद्रों के चलते वह संस्थागत रूप ले चुका है।

राजनीतिक दल गाहे–बगाहे इसके खिलाफ धीमी आवाज उठाते हैं, परन्तु किसी तरह की सर्वस्वीकृत आचार संहिता का विकास अभी तक नहीं हो सकता है। राजनीति करना एक महंगा काम बन चुका है, जिसके लिए धन की जरूरत पड़ती है, जो प्रायः नाजायज हथकण्डों के जरिये मिलता है पर धन के ये स्रोत बाद में अपनी कीमत वसूलते हैं और तब राजनेता उनके आगे झुकने के लिए लाचार रहता है। हवाला प्रकरण इस अन्तर्सम्बन्ध के एक नये पहलू की ओर संकेत करता है। धन की आमदनी के सातों का विस्तार विदेश में होना बहुतों को अन्तर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का एक हिस्सा लगता है, जो देश में अस्थिरता पैदा करना चाहता है।

पूर्व चुनावों में लोकसभा के नतीजों से जो संकेत मिला है वो पूर्णतः नहीं तो आंशिक तौर पर ही सही, एक सकारात्मक बदलाव का परिचायक भी है। इस बदलाव के लिए भारतीय जनता को मुख्य रूप से प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। चुनाव पूर्व मीडिया द्वारा जो उम्मीदवारों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया उसने जनमानस को बहुत हद तक झकझोड़ा और समस्या के प्रति संवेदनशील बनाया। प्रतिदिन मीडिया में कार्टून, लेखन तथा अन्य माध्यमों द्वारा वोटरों को अपने मत के महत्त्व के प्रति जागरूक करने का जो निरन्तर प्रयास किया गया दो वाकई काबिले तारीफ है। क्षेत्रीय अखबारों ने इस दिशा में अटूट परिश्रम किया तथा जनता को जगाया। प्रचंड गर्मी के कारण मतों का प्रतिशत भले ही आशा के अनुरूप नहीं रहा हो परन्तु जितने भी मत डाले गये उसमें ज्यादातर मत सोच समझकर डाले गये। जाति, धर्म, लिंग, भाई–भतीजावाद, भौतिक पदार्थों का लालच जैसे बहकाने वाले कारकों की भूमिका कम ही नजर आई।[5]

आम चुनावों का जनादेश कई अर्थों में ऐतिहासिक है। यह जितना अप्रत्याशित है, भविष्य की भारतीय राजनीति में उतनी ही दूर तक उसकी आवाज सुनाई देगी। संसद में अपराधियों की संख्या में भले ही बढ़ोतरी हुई हो परन्तु मतदाताओं ने कुछ हद तक यह साबित कर दिया कि महत्त्व के मौकों पर राष्ट्रहित का एक ही वैचारिक धागा उन्हें कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से गुजरात तक बाँधता है। जनादेश का पहला संदेश यह है कि यह राजनीतिक स्थिरता के पक्ष में है। जो चुनाव अभियान राजनीतिक गठबंधनों में बिखराव के साथ शुरू हुआ उसके निर्णायक अध्याय में भारत के मतदाताओं ने छोटे दलों की उच्छृखल भूमिका की गुंजाइश को खत्म कर दिया। खण्डित जनादेश राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनता है और राजनीतिक अस्थिरता का फायदा अपराधियों को मिलता है। सम्भावित राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाने की बेताब सभी छोटी व क्षेत्रीय पार्टियों को एक सबक मिल गया। जनादेश का अगला संदेश यह है कि मतदाताओं की निगाह भविष्य के भारत और युवा नेतृत्व तथा शासन में महिलाओं की भागीदारी पर टिकी है। युवाओं तथा महिलाओं के राजनीति में प्रवेश के माध्यम से भविष्य के भारत के लिए आशाएँ जगी है, क्योंकि ऐसा कई विचारकों का मानना है कि राजनीति में युवाओं तथा महिलाओं के प्रवेश से भ्रष्टाचार तथा अपराधीकरण जैसी समस्याओं में कमी आयेगी और आधुनिक, सम्पन्न और सफल भारत के निर्माण में एक बड़ा सहयोग मिलेगा। एक बड़ी संख्या में दागियों को नकार कर जनता ने राजनीति के अपराधीकरण की समस्या को गम्भीरता से लिया है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए सकरात्मक बदलाव है जिसके दूरगामी परिणाम होगे। मीडिया तथा गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका इस दिशा में सराहनीय है।[6]

वर्तमान में हमारे देश की राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण हो चला है। भाजपा को साम्प्रदायिक घोषित कर बहुत से राजनीतिक दलों ने अपने आप को धर्म निरपेक्षता का खिताब दिया, लेकिन सत्यता यह है कि वे धर्म निरपेक्षता की आड़ में जातिवाद को मोहरा बनाकर राजनीति में विशेषकर राज्यों की राजनीति में अनेक ऐसी प्रवृत्तियाँ देखने को मिल रही है, जो भारत की समन्वयता के लिए खतरा पैदा कर सकती है।

वर्तमान भारतीय राजनीति का जो परिदृश्य उभर रहा है वह पूर्णतः निराशाजनक है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे यहाँ स्वार्थ प्रेरित एक अलग तरह की राजनीतिक संस्कृति विकसित हो रही है जिसमें जनकल्याण, नैतिकता, आदर्श पालन, राष्ट्र प्रेम जैसी बातों को कोई स्थान नहीं है। एक तरफ राजनीति का अपराधीकरण हुआ है तो दूसरी तरफ अपराध का राजनीतिकरण एवं भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर हो रहा है।[7]

भारत में राजनीति मुख्यतः राष्ट्र–निर्माण और देश की एकता को बनाए रखने की राजनीति है। किसी भी परिवर्तन को इस दृष्टि से देखा जाता है कि उससे राष्ट्र की एकता को बल मिलेगा या नहीं। राजनीतिक स्थिरता की कुंजी सामाजिक व्यवस्था रही हैं अब यह सामाजिक व्यवस्था विखण्डित हो रही है और बदल रही है। भारतीय नेताओं के सामने यह चुनौती है कि यदि टूटती हुई सामाजिक संस्थाओं की जगह नई संस्थायें स्थापित नहीं की गई, यदि नए अवसर प्रस्तुत नहीं किए गए और नई मान्यताओं और मूल्यों की स्थापना नहीं की गई, तो राजनीतिक विकास के अवरूद्ध होने के साथ–साथ राजनीतिक व्यवस्था टूटने की स्थिति में आ सकती है।

अंग्रेजी के 'सी' अक्षर से शुरू होने वाले तीन शब्द करप्शन (भ्रष्टाचार), क्रिमनलाइजेशन (अपराधीकरण) और कास्टिज्म (जातीयता) हमारे राजनीतिक जीवन और व्यवस्था को खोखला कर रहे हैं। राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण का मेल खतरनाक साबित हो रहा है और इससे हमारे प्रजातंत्र में राजनीति के सामने गम्भीर समस्या आ खड़ी हुई है। सीधे तौर पर भ्रष्टाचार और अपराधीकरण का बेकारी, अशिक्षा, क्षीण स्वास्थ्य सेवाओं आदि जैसे भारत की समस्याओं पर सीधा असर पड़ता है।[8]

हमारी वर्तमान राजनीतिक प्रणाली की सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है, कि राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति में आज अपराध गिरोहों और माफियाओं का जोर साफ दिखायी देता है। राजनीति के अपराधीकरण की चर्चा पिछले दो–तीन आम–चुनावों से ज्यादा इसलिए होने लगी कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपराधियों की मदद ली जाने लगी। कालान्तर में राजनीतिज्ञों की मदद करने वाले अपराधी जब अपनी अहमियत समझने लगे स्वयं राजनीति में कूद पड़े और प्रशासन में भागीदारी भी बनने लगे। हालत यह हुई कि ये अपराधी धन–बल और भुजा–बल के सहारे राजनीति में इस कदर हावी हो गए कि इनके आगे साधारण व्यक्ति राजनीति से दूर होते चले गए। राजनीति में धनबल का वर्चस्व हो गया। इससे भ्रष्टाचार को बल मिला और फलस्वरूप प्रशासन की नीति–निर्माण का चेहरा भी बदशक्ल होने लगा। जनता के प्रति प्रशासन की संवेदनशीलता कम होती गई और धन (काला या सफेद) राजनीतिज्ञों व ऊँचे पदों पर बैठे अधिकारियों को प्रभावित करने लगा। हालात वर्तमान में ऐसे हो गये हैं कि एक–चौथाई सांसद ऐसे है, जिन पर अपराधीकरण के मामले चल रहे हैं।

चुनाव जीतने के लिए भी हर तरह के हथकण्डे अपनाए जाने लगे। इसके साथ ही जातिवाद ने जुड़कर 'करेला और नीम चढ़ा' की उक्ति चरितार्थ कर दी। आगे चलकर अपराधीकरण और जातिवाद ने साम्प्रदायिकता का रूप ले लिया, जिससे स्थिति और भी भयावह हो गई। चुनाव लड़ना साधारण व्यक्ति के बूते के बाहर की चीज हो गई।

'राजनीतिक अपराधीकरण' का एक दृश्य यह है कि देश में हिंसा को बेहद बढ़ावा मिला है, हिंसा के हथियारों का प्रयोग बहुत सामान्य हो गया है। गुण्डों को पैसा देकर जुटाया जाता है। अनेक प्रकार की सेनाएँ खड़ी की जाती है। राजनीतिक दलों द्वारा अक्सर उम्मीदवारों के चयन में गुण्डों तथा पैसे की ताकत को महत्त्व दिया जाता है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो की ओर से रिपोर्ट में कहा गया कि पूरे भारत में अपराधी तत्त्वों के गिरोह अपने नियम–कानून चला रहे हैं। यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों तक में भुजाबल वाले लोग अपना आतंक जमाते दिखाई देते हैं।[9]

अपराधी गिराहों पुलिस नौकरशाही और राजनीतिज्ञों के गठजोड़ का षड्यंत्रकारी रूप देश के विभिन्न भागों में सामने आ रहा है। गुप्तचर ब्यूरो की रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले कुछ वर्षों में अपराधी गिराहों और सशस्त्र गिरोहों के सरगना स्थानीय निकायों, विधानसभाओं और संसद तक में चुनकर पहुँचने लगे है। इस प्रकार के तत्त्वों द्वारा प्राप्त राजनीतिक शक्ति एक ओर प्रशासनिक स्तर पर रूकावटें पैदा करने लगी है, वहीं दूसरी ओर समाज के आम आदमी के जीवन और सम्पत्ति के लिए भी खतरा बनी हुई है।

'जैसा राजा, वैसी प्रजा' की लोकोक्ति बहुत पुरानी है। इसी सन्दर्भ में भारतीय राजनीति की चर्चा प्रासंगिक है कि जो भारतीय समाज में अपराधीकरण के मूल में है। एक जमाना था, जब राजा जनता के दुःखदर्द को प्रत्यक्षतः जानने और समझने के लिए वेष बदलकर घूमा करते थे। आज जनता का सेवक कमाण्डो से घिरा है जहाँ तक निरीह, असहाय और पीड़ित जनता की पहुँच ही सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में जनता और नेता का रिश्ता मात्र वोट मांगने तक सीमित हो गया है। भारतीय राजनीति में अस्थिरता का जो दौर प्रारम्भ हुआ, वह भी अपराधीकरण का एक दृश्य है।[10]

इसीलिए भारतीय राजनीति में अपराधी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति नेतृत्त्व की अगली पंक्ति में दिखाई दे रहे हैं। कल्पना कीजिए ऐसी लोकसभा और विधानसभाओं का जहाँ केवल चौराहों की गाली–गलौज और मारपीट जैसी घटनाओं के दृश्य आम हो जाएंगे, क्या जनता की आवाज वहां सुनाई देगी? ये सारी स्थितियां भी भारतीय समाज में अपराधीकरण के लिए उत्तरदायी है।[11]

वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य का मुख्य आधार दलीय स्वार्थों में फंसी राजनीति है। असंभव को संभव बनाने और झूठ को सच बताने की कला को राजनीति की एक परिभाषा के रूप में अक्सर समझा–समझाया जाता है। एक राजनीति प्रतीकों वाली होती है। इसमें राजनेता प्रतीकों वाले होते हैं। इसमें राजनेता प्रतीकों के सहारे अपने चेहरे चमकाने और मतदाता को भटकाने की कोशिश करते हैं। अक्सर राजनेता एक झूठ को इतनी बार दोहराते हैं कि सच लगने लगे और अक्सर वादों की इतनी बरसात कर देते हैं कि नेतागण भी मतदाता को ऐसे लगते हैं जैसे वे दावे कर रहे हैं। ये दावे इस तरह परोसे जाते हैं कि लगता है जैसे उपलब्धियों की थालियां सजाकर सामने रख दी गई हों।[12] इस राजनीति का एक चेहरा और भी है। दूसरों की लकीर को छोटा दिखाने वाला चेहरा । यह तरीका भी दावों और वादों की राजनीति जितना ही कारगर समझा जाता है। जैसे यह मान लिया जाता है कि लोग वादे भूल जाते हैं, वैसे ही हमारे राजनेता यह मानकर चलते हैं, वैसे ही हमारे राजनेता यह मानकर चलते हैं कि प्रतिद्वंद्वी राजनेताओं को छोटा दिखाकर या छोटा बनाकर वे जनता को भटका सकते है।

राजनीति में आपराधिक तत्त्वों का लगातार बढ़ता प्रभाव लोकतंत्र के लिए बढ़ते खतरे का ही संकेत है। जब कोई राजनीतिक दल लोकतंत्र की पवित्रता को ताक पर रखकर किसी ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाता है जिसके दामन दागदार रहे हो, तो बात सिर्फ उसके जीतने–हारने तक ही सीमित नहीं रहती। जीतने के

बाद वह जनप्रतिनिधि होने का तमगा लगाकर लोकतांत्रिक ताने–बाने को तहस–नहस करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। यह कहना ज्यादा उचित होगा कि ऐसा व्यक्ति लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनी ताकत के लिए लगातार खतरा महसूस करता रहता है और इसे कमजोर करने में ही अपना हित देखता है। जाहिर है, दागी व्यक्ति का छोटी बड़ी किसी भी पंचायत का सदस्य बन जाना देश को दीमक के हवाले करने जैसा है। आंकड़ों पर गौर करते ही यह बात एकदम साफ हो जाती है कि राजनीति में मूल्यों का ह्रास आखिर क्यों हो रहा है। 2004 में 24 प्रतिशत, 2009 में 30 प्रतिशत, 2014 में 34 प्रतिशत आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवार लोकसभा तक पहुँचने में सफल रहे। यदि यही सिलसिला जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं, जब आधे से ज्यादा लोकसभा सदस्य आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे। चुनौतीपूर्ण समस्या होने के बावजूद किसी राजनीतिक दल ने इस आसन्न खतरे के प्रति सजगता का प्रदर्शन नहीं किया है। ताजा मामला दिल्ली विधानसभा चुनाव का है जिसमें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्स के मुताबिक 70 में से 43 विधायकों की पृष्ठभूमि आपराधिक है।[13]

निष्कर्ष – आज भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ भी आशाजनक नहीं कहा जा सकता। राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, नेतागण अपनी कथित उपलब्धि के विवरण के साथ अपनी फोटो अखबारों में छपवा रहे हैं। उनकी उपलब्धियों हैंकृचारों तरफ फैले कूड़े के ढेर; बढ़ती महंगाई, इंसानियत का सफाया और संवेदना का अभाव, जिनके बलबूते वे अपना ढिंढोरा स्वयं पीट रहे हैं। विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में हमारा दबदबा हो चुका है लेकिन राजनीति को अपराध से मुक्ति नहीं मिल सकी। लेकिन यह तभी लाभदायक है जब उसके लिए वातावरण सुधरेगा। राष्ट्र स्तरीय विशेष अवसरों पर भ्रष्टाचार, राजनीति का अपराधीकरण, साम्प्रदायिकता और जातिवाद की बुराइयों को रेखांकित किया जा रहा है, उत्साही नागरिकों, प्रेस और न्यायपालिका से इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सहयोग का आह्वान भी किया जा रहा है।

राजनीति में अपराधियों की बढ़ती भागीदारी तो चिंता का विषय है ही, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसे सांसद स्थानीय विकास को भी नुकसान पहुँचा सकते है। इनका ध्यान स्थानीय लोगों के विकास पर ज्यादा नहीं रहता है। निशिथ प्रकाश और अन्य ने एक अध्ययन करके बताया था, कि गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि के आरोपी को चुनने से चुनाव क्षेत्र में आर्थिक विकास में काफी कमी आती है, राजनीति में इस समस्या को दूर करने के लिए बहुकोणीय दृष्टिकोण के साथ काम करना होगा। चुनावी वित्त सुधार और राज्य की क्षमता में सुधार करना पड़ेगा, तब जाकर भारतीय राजनीति में धन और अपराध की प्रवृत्ति से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन राजनीति में अपराधों की कोई कमी नहीं है।

वर्तमान में भारतीय राजनीति में अपराधीकरण एक चैन की तरह फैला हुआ है जिसकी कड़ी तोड़ने के लिए जनता, नेता, प्रशासन, विधायिका एवं न्याय आदि को ईमानदारी पूर्ण कार्य करते हुए नैतिक नियमों का पालन करना होगा।

संदर्भ ग्रंथ

1. निबंध मंजूषा : समीरात्मज मिश्र, पब्लिकेशन हिल एज्युकेशन, 1 जून 2016, पृ. सं.–37
2. भारत की आन्तरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबन्धन, उदयभान सिंह, अमन कुमार, पृ. सं. 19, 20
3. "जनादेश का बदलता संदेश', दैनिक भास्कर, 18 फरवरी 2019, पृ. सं.–08
4. आज की राजनीति और भ्रष्टाचार, नरेन्द्र मोहन, पृ. सं.–102
5. 'राजनीतिक अपराधीकरण', इंडियन एक्सप्रेस, 2 अगस्त 2015, पृ. सं.–14
6. दलीय स्वार्थों में फँसी राजनीति, दैनिक नवज्योति, 26 अक्टूबर 2018, पृ. सं.–05
7. सांसद बारहवीं से अधिक नहीं पढ़े, एक निरक्षर भी'– राजस्थान पत्रिका एवं नेशनल इलेक्शन वॉच (एडीआर रिपोर्ट), 30 मार्च 2019– पृ. सं.–8
8. "सियासत में अपराध'–राजस्थान पत्रिका, 5 दिसम्बर 2018, पृ. सं.–12
9. "यौन हिंसा, हत्या एवं अपराध', भारत सरकार सांख्यिकी रिपोर्ट, राजस्थान पत्रिका, 16 मार्च 2019, पृ. सं.–10
10. "मोदी के अपराध मुक्त राजनीति के वादें", विशाल जयसवाल, द वायर, 26 अप्रैल 2019, पृ. सं.–10
11. "राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण', अरविंद जैन, द फारवर्ड प्रेस, 31 मार्च 2019
12. राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण, लोकसभा और राज्यसभा टी वी डिबेट, 18 फरवरी, 2020
13. ''भारतीय राजनीति में धन और अपराध की बढ़ती धमक'', महासंग्राम लोकसभा चुनाव, राजस्थान पत्रिका, 22 मई 2019, पृ.सं. 09